



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15820

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आदेश से प्रथम अपील संख्या - 2491/2019

मोहम्मद जहीर

..... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

चेयरमैन यू.पी.एस.आर.टी.सी. लखनऊ जरिए ए.आर.एम.

..... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : अंजू शुक्ला, निगमेन्द्र शुक्ला

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : एस.के. मिश्रा

एवं एक अन्य वाद सम्बद्ध।

न्यायालय संख्या - 38

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

1. एफ.ए.एफ.ओ. संख्या 1698 वर्ष 2008, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत, वाहन स्वामी यूपीएसआरटीसी द्वारा अपील के रूप में दायर की गई है, जिसमें दिनांक 17.03.2008 को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-7, मेरठ द्वारा मोटर दुर्घटना दावा वाद संख्या 682 वर्ष 2004 (मोहम्मद जहीर बनाम यूपीएसआरटीसी) में पारित निर्णय एवं अधिनिर्णय को चुनौती दी गई है। उक्त निर्णय के द्वारा, दिनांक 18.12.2003 को घटित सड़क दुर्घटना में वादी को हुई चोटों के लिए ₹1,98,600/- की क्षतिपूर्ति, 6% वार्षिक ब्याज सहित, प्रदान की गई थी, जिसे अपकारी बस संख्या UP-21L-0405 के स्वामी यूपीएसआरटीसी द्वारा वहन किए जाने का आदेश दिया गया था।

2. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 7, मेरठ द्वारा 2004 की मोटर दुर्घटना दावा याचिका संख्या 682 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/अतिरिक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 7, मेरठ द्वारा पारित दिनांक 17.03.2008 के आक्षेपित निर्णय और निर्णय के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत मुआवजे में वृद्धि के लिए दावेदार द्वारा एफएफओ संख्या 2491/2019 (मो0 जहीर बनाम यूपीएसआरटीसी)को भी प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत 18.12.2003 को हुई सड़क दुर्घटना में दावेदार को लगी चोटों के लिए, दावेदार को 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 1,98,600/- रुपये का मुआवजा दिया गया है, जिसे आपत्तिजनक बस संख्या यूपी-21एल-0405 के मालिक-यूपीएसआरटीसी द्वारा क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया गया है।

3. चूंकि, दोनों अपीलें एक ही आक्षेपित निर्णय और अधिनिर्णय से उत्पन्न होती हैं, इस तरह, उन्हें इस सामान्य निर्णय द्वारा एक साथ सुना और तय किया जा रहा है।

4. अपीलकर्ता-यूपीएसआरटीसी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दावेदार ने आरोप लगाया कि दुर्घटना की तारीख को, वह स्कूटर संख्या डीएल-1-एसबी-0460 पर पीछे बैठे के रूप में यात्रा कर रहा था, जो अपमानजनक बस संख्या यूपी-21-एल-0405 से टकरा गया, जो पूरी तरह से असंभव था।

5. यह प्रस्तुत किया गया था कि दुर्घटना का तथ्य पूरी तरह से संदिग्ध था और यहां तक कि अगर यह मान लिया जाता है कि दुर्घटना वास्तव में हुई थी, तब भी, रिकॉर्ड पर सबूतों से, यह साबित हुआ था कि यह स्कूटर चालक की एकमात्र लापरवाही के कारण हुआ था, जिसे दावा याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि न्यायाधिकरण ने गलती से निष्कर्ष निकाला है कि स्कूटर चालक की केवल 40% अंशदायी लापरवाही थी, जबकि, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार, यह 100% थी।

6. इन प्रस्तुतियों के साथ, यह प्रार्थना की गई थी कि अपील की अनुमति दी जाए और दावा याचिका खारिज कर दी जाए।

7. प्रति-प्रतिवादी, दावेदार-प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से, यह साबित हुआ कि दुर्घटना आमने-सामने हुई थी, जब दावेदार उपरोक्त स्कूटर पर पीछे बैठे के रूप में यात्रा कर रहा था और दुर्घटना के समय, आपत्तिजनक बस को जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया जा रहा था।



8. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि दावेदार को लगी चोटों के कारण, घुटने के नीचे उसका दाहिना पैर काट दिया गया था, जिसके कारण, उसे 100% कार्यात्मक अक्षमता का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वह साड़ी की दुकान में सेल्समैन के रूप में काम करने में असमर्थ था।

9. यह प्रस्तुत किया गया था कि दुर्घटना से पहले, दावेदार एक साड़ी की दुकान में एक सेल्समैन के रूप में काम कर रहा था, लेकिन उसके द्वारा झेली गई स्थायी अक्षमता के कारण दुर्घटना के बाद, वह उस काम को करने में असमर्थ था, जो उसके नियोक्ता पीडब्लू -2 संजय के साक्ष्य से भी साबित हुआ था, लेकिन फिर भी न्यायाधिकरण ने इस आधार पर मुआवजे का आकलन किया है कि दावेदार को केवल 50% कार्यात्मक अक्षमता का सामना करना पड़ा था, जैसा कि स्थायी अक्षमता प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया था, जो गलत था।

10. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण अक्षमता प्रमाण पत्र में उल्लिखित स्थायी अक्षमता के प्रतिशत से बाध्य नहीं था और उसे स्वतंत्र रूप से कार्यात्मक अक्षमता की मात्रा का आकलन करना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा है।

11. यह भी प्रस्तुत किया गया कि दावेदार **उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 220-ए** के अनुसार 50% की दर से स्थायी अक्षमता के कारण भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार था; हालांकि, न्यायाधिकरण ने इस मद के तहत कोई मुआवजा नहीं दिया है।

12. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि न्यायाधिकरण ने गैर-आर्थिक मदों के तहत अपर्याप्त मुआवजा दिया है और 6% प्रति वर्ष की दर से मुआवजे पर ब्याज दिया है, जबकि, उपरोक्त नियमों के तहत, दावेदार 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार था।

13. इन प्रस्तुतियों के साथ, यह प्रार्थना की गई थी कि बीमा कंपनी द्वारा पसंद की गई अपील को खारिज कर दिया जाए, और मुआवजे में वृद्धि के लिए दावेदार द्वारा पसंद की गई अपील की अनुमति दी जाए।

14. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और निचली अदालत के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

15. न्यायाधिकरण के सामने, दावेदार ने खुद को पीडब्लू-1, संजय को पीडब्लू-2 के रूप में, डॉ. राजीव सिंह को पीडब्लू-3 के रूप में, मो. उस्मान को पीडब्लू-4 के रूप में, डॉ. रवींद्र सिंह को



पीडब्लू-5 के रूप में और डॉ. प्रवीण जैन को पीडब्लू-6 के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि, यूपीएसआरटीसी द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया था।

16. दावेदार, मो. जहीर पीडब्लू-1 ने गवाही दी कि दुर्घटना के दिन, वह मेरठ-मवाना रोड से स्कूटर पर पीछे बैठने वाले यासीन के साथ यात्रा कर रहा था, फिर डेयरी के सामने छोटा मवाना में, एक ट्रांसफार्मर के पास, एक रोडवेज बस नं. यूपी-21-एल-0405, जिसे उसके चालक द्वारा तेज और लापरवाही से चलाया जा रहा था, विपरीत दिशा से आया, और बस ने सड़क के गलत साइड में आकर उसके स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसके कारण वह नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, यह दुर्घटना दोपहर 3:30 बजे हुई। इस हादसे में उनका दाहिना पैर बुरी तरह से कुचल गया था, उनके शरीर में 31 टांके लग गए थे, उन्हें दिव्य ज्योति अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह करीब 15 दिनों तक उस अस्पताल में भर्ती रहे। उन्होंने आगे बयान दिया कि दुर्घटना में लगी चोटों के कारण, उनका दाहिना पैर कुचल गया था और घुटने के नीचे काट दिया गया था।

17. उन्होंने आगे गवाही दी कि दुर्घटना के समय, स्कूटर को यासीन द्वारा सड़क के बाईं ओर नियंत्रित गति से चलाया जा रहा था। उन्होंने आगे बयान दिया कि दुर्घटना से पहले, वह भाविक साड़ी सेंटर, मवाना में काम कर रहे थे और उन्हें 3,600 रुपये प्रति माह का वेतन मिल रहा था, लेकिन दुर्घटना में स्थायी अक्षमता के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और अब वह काम करने में सक्षम नहीं हैं। उनका परिवार उनकी आय पर निर्भर था। अब उन्हें आय का कोई स्रोत नहीं मिला है। उन्होंने आगे बयान दिया कि उन्होंने अपना स्थायी अक्षमता प्रमाण पत्र दाखिल किया है, जो प्यारे लाल शर्मा अस्पताल, मेरठ से प्राप्त किया गया था। जिरह में, दावेदार ने गवाही दी कि आपत्तिजनक बस बड़ा मवाना की ओर से सामने से आई थी। वह छोटा मवाना से बड़ा मवाना जा रहा था, हादसे के बाद वह बेहोश हो गया। राहगीर ने उसे दिव्य ज्योति नर्सिंग होम, गंगानगर, मेरठ में भर्ती कराया और पांच दिन बाद उसे होश आ गया।

18. जिरह के दौरान, उसने गवाही दी कि वह लंबे समय तक खड़ा नहीं हो सकता है और अदालत से अनुरोध किया कि वह उसे एक कुर्सी पर बैठने की अनुमति दे, और उसकी जिरह एक कुर्सी पर बैठकर आयोजित की गई। उन्होंने आगे बयान दिया कि दुर्घटना के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्होंने आगे बयान दिया कि एक सेल्समैन के रूप में, वह साड़ी, लेडीज सूट सलवार, पैंट शर्ट के टुकड़े बेचता था और उसका काम उपरोक्त वस्तुओं को ले जाना, उन्हें मोड़ना, उन्हें



दुकान में उचित स्थान पर रखना था और साथ ही वह दुकान पर आने वाले प्रस्तावित खरीदारों को उपरोक्त कपड़े प्रदर्शित करता था।

19. दावेदार संजय के नियोक्ता की पीडब्लू-2 के रूप में विवेचना की गई, जिसने गवाही दी कि वह मवाना में मेसर्स भाविक साड़ी सेंटर के नाम और शैली में एक दुकान का मालिक है, जिसमें दावेदार काम करता था, जिसे नकद में प्रति माह 3,600/- रुपये का वेतन दिया जा रहा था। इस गवाह ने दावेदार के वेतन प्रमाण पत्र को साबित कर दिया है। उन्होंने आगे गवाही दी कि दुर्घटना में, दावेदार का दाहिना पैर घुटने के नीचे काट दिया गया है, जिसके कारण, वह अब कोई काम नहीं कर पा रहा है और इस कारण से, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और उसने दावेदार के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया है। जिरह में, इस गवाह ने गवाही दी कि उसने दावेदार के स्थान पर असलम नामक एक व्यक्ति को नियुक्त किया है, जिसे दावेदार को उतना ही वेतन दिया जा रहा था जितना दावेदार को दिया जा रहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें दावेदार को वेतन के भुगतान का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने खुलासा किया कि वह अपनी दुकान से प्रति माह लगभग 20,000 रुपये कमा रहे थे। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि दावेदार उसकी दुकान पर कार्यरत नहीं था, जिसे 3,600 रुपये प्रति माह का वेतन नहीं दिया जा रहा था।

20. डॉ. राजीव सिंह पीडब्लू-3 ने गवाही दी कि 18.12.2003 को दुर्घटना में दावेदार को लगी चोटों के कारण, उसका लीवर टूट गया था और दाहिना पैर कुचल गया था, जिसका उसके द्वारा ऑपरेशन किया गया था और पैर घुटने के नीचे काट दिया गया था और दावेदार 18.12.2003 से 02.01.2004 तक अपने अस्पताल में भर्ती रहा। जिरह में, उसने गवाही दी कि दावेदार का पैर उसके नर्सिंग होम में काट दिया गया था।

21. मो. उस्मान पीडब्लू-4 ने 18.12.2003 को दोपहर लगभग 3:30 बजे मेरठ पर गवाही दी? (ख) यदि हां, तो दावेदार अपने भाई यासीन के स्कूटर पर यात्रा कर रहा था। यूपी-21-एल-0405, जिसे तेज और लापरवाही से चलाया जा रहा था, सड़क के गलत साइड में आ गया और स्कूटर से आमने-सामने टकरा गया, जिसके परिणामस्वरूप स्कूटर पर यात्रा करने वाले व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने आगे बयान दिया कि वह और मौके पर मौजूद अन्य व्यक्ति घायलों को इलाज के लिए डीसीएम वाहन में दिव्य ज्योति नर्सिंग होम, गंगानगर, मेरठ ले गए, जहां दावेदार को भर्ती कराया गया था। आपत्तिजनक बस के चालक को पकड़ लिया गया और कुछ ही



देर बाद पुलिस भी पहुंची जिसे आपत्तिजनक बस के चालक को सौंप दिया गया। उन्होंने आगे बयान दिया कि उन्होंने शाम 5:30 बजे मवाना पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी और इस प्रकरण में साइट प्लान भी तैयार किया गया था। जिरह में, इस गवाह ने गवाही दी कि उसने दुर्घटना को लगभग एक सौ मीटर की दूरी से देखा था और स्कूटर उसके भाई मो. यासीन। उसने स्वीकार किया कि उसने खुद पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी, लेकिन किसी राहगीर ने पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने यह भी बताया कि दुर्घटना के बाद सड़क पर भीड़ जमा हो गई थी और यातायात जाम हो गया था। उन्होंने आगे बयान दिया कि बस के चालक पक्ष ने स्कूटर से टक्कर मार दी और पुलिस की मदद से दावेदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने आगे स्वीकार किया कि वह दुर्घटना के बारे में परिवार के सदस्यों को सूचित करने के लिए अपने घर गया था, लेकिन उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसने दुर्घटना नहीं देखी थी और दुर्घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि दुर्घटना स्कूटर चालक के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी।

22. पीडब्लू-5 डॉ. रवींद्र सिंह, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ, जिला अस्पताल, मेरठ की विवेचना पीडब्लू-5 के रूप में की गई थी, जिन्होंने दावेदार को जारी किए गए अक्षमता प्रमाण पत्र को साबित कर दिया है, जिसमें खुलासा किया गया है कि घुटने के नीचे दाहिने पैर के विच्छेदन के कारण उन्हें 50% की स्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ा है। उन्होंने आगे गवाही दी कि अक्षमता के कारण, दावेदार को अपने दैनिक दिनचर्या के काम करने में कठिनाई हो रही होगी, और वह किसी भी काम को करने से और भी अक्षम हो गया था, जो वह दुर्घटना से पहले कर रहा था। जिरह में, यह गवाह स्थायी अक्षमता के कारण दावेदार को हुई कार्यात्मक अक्षमता का खुलासा करने में विफल रहा। उन्होंने यह भी गवाही दी कि दावेदार के पेट का भी ऑपरेशन किया गया था।

23. यह स्पष्ट है कि बीमा कंपनी ने इस गवाह (पीडब्लू -5) की जिरह नहीं की है कि क्या दावेदार दुर्घटना में उसके द्वारा स्थायी अक्षमता के बाद भी साड़ी की दुकान में सेल्समैन के रूप में काम कर सकता है।

24. दावेदार ने डॉ. प्रवीण जैन की पीडब्लू-6 के रूप में भी विवेचना की, जिन्होंने गवाही दी कि वह एक प्लास्टिक सर्जन थे, जिन्होंने 18.12.2003 को दिव्य ज्योति स्पेशलिटी अस्पताल,



गंगानगर, मेरठ में दावेदार का इलाज किया था, जिन्होंने दावेदार के घायल दाहिने पैर की विवेचना की थी, जो घुटने के नीचे बुरी तरह से कुचला हुआ पाया गया था, जिसमें दोनों हड्डियां फ्रैक्चर पाई गईं और टखने के जोड़ की यौगिक अव्यवस्था भी थी और सभी मांसपेशियों को भी कुचल दिया गया था। उन्होंने आगे गवाही दी कि दावेदार के दाहिने पैर में कोई संवेदना, हलचल या रक्त प्रवाह नहीं था और इसलिए उन्होंने घुटने के नीचे दाहिने पैर को काटने की सलाह दी थी। उन्होंने आगे 18.12 को गवाही दी। वर्ष 2003 में उन्होंने डॉ. मनोज गुप्ता और डॉ. राजीव सिंह के साथ मिलकर दावेदार के घुटने के नीचे का दाहिना पैर काट दिया था। डॉ. राजीव सिंह ने दावेदार के पेट का ऑपरेशन किया था, जबकि डॉ. ए. मुखर्जी एनेस्थेतिस्ट के रूप में मौजूद थे।

25. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रजनी साहू और अन्य (2025) 2 एससीसी 599 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है: -

"8. मोटर दुर्घटना के प्रकरण में विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा एकत्र किए गए आरोप-पत्र और अन्य दस्तावेजों की विश्वसनीयता के संबंध में, इस न्यायालय ने मंगला राम बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [(2018) 5 एससीसी 656: (2018) 3 एससीसी (सीआईवी) 335: (2018) 2 एससीसी (सीआरआई) 819: 2018 आईएनएससी 311], पैरा 27 में अभिनिर्धारित किया था, इस प्रकार : (एससीसी पृष्ठ 672)

"27. एक अन्य कारण जो प्रतिवादी 2 और 3 द्वारा दायर पहली अपील में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय के साथ तौलता गया था, वह विषय जीप के चालक की लापरवाही के तथ्य के बारे में न्यायाधिकरण द्वारा निष्कर्ष निकालने का अभाव था। वास्तव में, यह दृष्टिकोण असमर्थनीय है। अधिकरण द्वारा किए गए विश्लेषण के बारे में हमारी समझ यह है कि जीप नं. RST 4701 को प्रतिवादी 2 द्वारा लापरवाही से और लापरवाही से चलाया गया था जब यह अपीलकर्ता की मोटरसाइकिल से टकरा गया जिससे दुर्घटना हुई। यह गवाहों के साक्ष्य और पुलिस द्वारा दायर आरोप-पत्र की सामग्री से समझा जा सकता है, जिसमें प्रतिवादी 2 का नाम दिया गया है। इस न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में डुलसीना फर्नांडीस [डुलसीना फर्नांडीस बनाम जोआकिम जेवियर क्रूज़, (2013) 10 एससीसी 646: (2014) 1 एससीसी (सीआईवी) 73: (2014) 1 एससीसी (सीआरआई) 13], नोट किया गया कि दावेदारों द्वारा स्थापित आपत्तिजनक वाहन के चालक की ओर से लापरवाही की कुंजी को न्यायाधिकरण द्वारा संभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर तय करने की आवश्यकता थी और निश्चित रूप से उचित से परे सबूत के मानक द्वारा नहीं



संदेह। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि हमारे द्वारा पहले से ही विज्ञापित निर्णयों में व्याख्या, प्रतिवादी 2 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रथम दृष्टया लापरवाही और जल्दबाजी में वाहन चलाने में उसकी मिलीभगत की ओर इशारा करता है। इसके अलावा, जब आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त को बरी किया जाना था, तब भी इस न्यायालय ने राय दी कि न्यायाधिकरण द्वारा मोटर दुर्घटना के प्रकरण के संबंध में आवश्यक दायित्व के आकलन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

9. यह सच है कि न्यायाधिकरण ने एफआईआर, अंतिम रिपोर्ट और विचाराधीन दुर्घटना के संबंध में पुलिस द्वारा तैयार किए गए ऐसे अन्य दस्तावेजों सहित मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना की थी। न्यायाधिकरण ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया था कि अंतिम रिपोर्ट के आधार पर, आपत्तिजनक ट्रक के चालक पर मुकदमा चलाया गया और उसे लापरवाही से गाड़ी चलाने का दोषी पाया गया। उच्च न्यायालय ने ऐसे पहलुओं पर ध्यान दिया और न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई अवैधता नहीं पाई और परिणामस्वरूप अपील को खारिज कर दिया।

10. प्रासंगिक स्थिति में मैथ्यू अलेक्जेंडर बनाम मो. शफी [(2023) 13 एससीसी 510: 2023 आईएनएससी 621], इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पी. 514, पैरा 12)

“12. न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य के समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिए और दावेदारों द्वारा किसी विशेष वाहन के कारण होने वाली दुर्घटना के सख्त प्रमाण को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। दावेदारों को संभावनाओं की प्रधानता की कसौटी पर अपना प्रकरण स्थापित करना होगा। सड़क यातायात दुर्घटना में मृत्यु या चोट के कारण मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर विचार करते समय उचित संदेह से परे प्रमाण के मानक को लागू नहीं किया जा सकता है। इसी आशय के लिए इस न्यायालय द्वारा डुलसीना फर्नांडीस बनाम जोआकिम जेवियर क्रूज़ [(2013) 10 एससीसी 646: (2014) 1 एससीसी (सीआईवी) 73: (2014) 1 एससीसी (सीआरआई) 13] में की गई टिप्पणी है, जिसमें बिमला देवी [बिमला देवी बनाम हिमाचल आरटीसी, (2009) 13 एससीसी 530: (2009) 5 एससीसी (सीआईवी) 189 में पूर्वोक्त निर्णय का उल्लेख किया गया है: (2010) 1 एससीसी (सीआरआई) 1101] .?”

11. इस प्रकार, इस स्थिति के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि लापरवाही के बारे में प्रश्न जो मोटर वाहन दुर्घटना के दावे में एक अधिनिर्णय पारित करने के लिए आवश्यक है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायाधिकरण के समक्ष उपलब्ध सबूतों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। यदि न्यायाधिकरण के समक्ष पुलिस रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, तो अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि उपरोक्त उद्देश्य के लिए ऐसे दस्तावेजों को देखना अस्वीकार्य या अस्वीकार्य है।

12. यह भी एक तथ्य है कि अपीलकर्ता ने कहा था कि प्रतिवादी दावेदारों ने पुलिस के साथ मिलीभगत की और धोखाधड़ी से आरोप पत्र तैयार किया। तर्क यह है कि अपीलकर्ता के साथ बीमित वाहन दुर्घटना में शामिल नहीं था और दुर्घटना केवल मृतक की ओर से दाने और लापरवाही के कारण हुई थी। लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलेगा कि अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद, तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने का संज्ञान लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उदयनाथ साहू की मौत हो गई थी।

(प्रभाव वर्द्धित)

26. रंजीत और अन्य बनाम अब्दुल कयाम नेब और अन्य 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 497 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है: -

"4. कानून में यह तय है कि एक बार आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और चालक को लापरवाही से दोषी ठहराया गया है, यह साबित करने के लिए किसी और सबूत की आवश्यकता नहीं है कि बस चालक द्वारा लापरवाही से बस चलाई जा रही थी। अगर चश्मदीद गवाहों से पूछताछ नहीं की जाती है, तो भी बस चालक की लापरवाही के कारण मृतक की मौत साबित करना घातक नहीं होगा।

(प्रभाव वर्द्धित)

27. दावेदार पीडब्लू-1 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह स्कूटर संख्या पर पीछे बैठे व्यक्ति के रूप में यात्रा कर रहा था। दुर्घटना के समय डीएल-1-एसबी-0460 था, फिर आपत्तिजनक बस विपरीत दिशा से आई और स्कूटर से आमने-सामने टकरा गई, जिसका यूपीएसआरटीसी ने न्यायाधिकरण के समक्ष उल्लंघन करने वाली बस के चालक की विवेचना करके खंडन नहीं किया था।

28. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि लापरवाही के निष्कर्ष का खंडन करने के लिए, उल्लंघन करने वाले चालक की अपीलकर्ता-यूपीएसआरटीसी द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष विवेचना की जानी चाहिए, लेकिन इसके द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था।

29. यह भी स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण ने मोहम्मद मोहम्मद की गवाही पर अविश्वास किया है। उस्मान पीडब्लू-4 ने इस आधार पर कहा कि दुर्घटना के बाद वह दुर्घटना के बारे में परिवार के सदस्यों को सूचित करने के लिए अपने घर गया था, जो असामान्य था, इस प्रकार, वह दुर्घटना का चश्मदीद गवाह नहीं हो सकता है, जो एक विकृत खोज है।

30. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि दावेदारों को दुर्घटना और उल्लंघन करने वाले बस चालक की लापरवाही को उचित संदेह से परे साबित नहीं करना चाहिए और केवल उन्हें संभावनाओं की प्रबलता पर इसे साबित करना होगा, जिसे उन्होंने साबित किया है।

31. यह दावेदार के साक्ष्य से साबित हुआ, जो एक घायल गवाह और प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू -4 था, कि दुर्घटना के समय, स्कूटर को सड़क के बाईं ओर ले जाया जा रहा था, जिसे आपत्तिजनक बस ने टक्कर मार दी थी, इस तरह, न्यायाधिकरण के लिए यह मानने का कोई अवसर नहीं था कि स्कूटर चालक ने दुर्घटना में 40% का योगदान दिया।

32. केवल इस आधार पर कि स्कूटर चालक की दाहिनी हथेली और दावेदार का दाहिना पैर बस के शरीर के संपर्क में आया था, यह नहीं माना जा सकता है कि यदि स्कूटर चालक सतर्क होता, तो दुर्घटना को टाला जा सकता था। यह स्पष्ट है कि चूंकि दावेदार का दाहिना पैर घायल हो गया था, इसलिए न्यायाधिकरण ने दुर्घटना में स्कूटर चालक की समग्र लापरवाही को माना है, जो एक विकृत निष्कर्ष है। यह भी स्पष्ट है कि चूंकि स्कूटर चालक दावा याचिका में पक्षकार नहीं था, इसलिए समग्र लापरवाही का यह निष्कर्ष न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज नहीं किया जा सकता था और **खेनेई बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (2015) 9 एससीसी 273** के प्रकरण में शीर्ष न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, दावेदार किसी भी अपकृत्य से मुआवजे का दावा करने का हकदार था यानी या तो स्कूटी चालक से या बस चालक से / मालिक लेकिन दावेदार ने बस, यूपीएसआरटीसी के मालिक से मुआवजे का दावा करने का विकल्प चुना है।



33. जहां तक स्कूटर के चालक की अंशदायी लापरवाही का संबंध है, न्यायाधिकरण के उपरोक्त निष्कर्ष को अलग रखा जा सकता है और तदनुसार इसे अलग रखा जाता है और यह माना जाता है कि दुर्घटना आपत्तिजनक बस नंबर के चालक की एकमात्र लापरवाही के कारण हुई थी। यूपी-21-एल0405 को दुर्घटना के समय तेज और लापरवाही से चलाया जा रहा था।

34. यह भी स्पष्ट है कि आपराधिक प्रकरण में विवेचना के बाद अपराध करने वाले बस चालक मो. असलम ने आईपीसी की धारा 279, 337, 338, 427 के तहत प्रकरण दर्ज किया है, जिस पर सक्षम आपराधिक अदालत ने संज्ञान लिया है, जिसकी यूपीएसआरटीसी द्वारा विवेचना नहीं की गई है, यह साबित करने के लिए कि वह दुर्घटना के समय अपनी बस को नियंत्रित गति से सावधानी से चला रहा था और दुर्घटना में उसकी ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई थी।

35. पीडब्लू-3, पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 के साक्ष्य से यह साबित हुआ कि दुर्घटना में दावेदार को लगी चोटों के कारण उसका दाहिना पैर बुरी तरह से कुचल गया था, जिसे घुटने के नीचे काट दिया गया था, जिसके कारण उसे 50% स्थायी अक्षमता का सामना करना पड़ा है, जो पीडब्लू-5, डॉ. रवींद्र सिंह की विवेचना से साबित हुआ था।

36. **राज कुमार बनाम अजय कुमार और अन्य (2011) 1 एससीसी 343** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थायी अक्षमता के प्रकरण में मुआवजे का निर्धारण करने के तरीके का विश्लेषण करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था दी है: -

10. जहां दावेदार चोटों के परिणामस्वरूप एक स्थायी अक्षमता का सामना करता है, भविष्य की कमाई के नुकसान के सिर के तहत मुआवजे का आकलन उसकी कमाई की क्षमता पर इस तरह की स्थायी अक्षमता के प्रभाव और प्रभाव पर निर्भर करेगा. न्यायाधिकरण को स्थायी अक्षमता के प्रतिशत को आर्थिक हानि या कमाई क्षमता के नुकसान के प्रतिशत के रूप में यांत्रिक रूप से लागू नहीं करना चाहिए। ज्यादातर प्रकरण में, आर्थिक नुकसान का प्रतिशत, यानी स्थायी अक्षमता से उत्पन्न होने वाली कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत स्थायी अक्षमता के प्रतिशत से अलग होगा। कुछ न्यायाधिकरण गलत तरीके से मानते हैं कि सभी प्रकरण में, स्थायी अक्षमता की एक विशेष सीमा (प्रतिशत) के परिणामस्वरूप कमाई की क्षमता का नुकसान होगा, और परिणामस्वरूप, यदि उत्पादित साक्ष्य दिखाते हैं 45% स्थायी अक्षमता के रूप में, यह मानेंगे कि भविष्य की कमाई क्षमता का 45% नुकसान होता है। अधिकांश प्रकरण में, स्थायी अक्षमता की सीमा (प्रतिशत)



तक अर्जन क्षमता के नुकसान की सीमा (प्रतिशत) के बराबर करने पर या तो बहुत कम या बहुत अधिक मुआवजा दिया जाएगा।

11. न्यायाधिकरण द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि घायल की कमाई की क्षमता पर स्थायी अक्षमता का प्रभाव है; और आय के प्रतिशत के संदर्भ में कमाई की क्षमता के नुकसान का आकलन करने के बाद, इसे पैसे के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए, कमाई के भविष्य के नुकसान पर पहुंचने के लिए (निर्भरता के नुकसान को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक गुणक विधि को लागू करके)। हालांकि हम ध्यान दे सकते हैं कि कुछ प्रकरण में, साक्ष्य और मूल्यांकन की सराहना पर, न्यायाधिकरण यह पा सकता है कि स्थायी अक्षमता के परिणामस्वरूप कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत, स्थायी अक्षमता के प्रतिशत के समान है, जिस प्रकरण में, निश्चित रूप से, न्यायाधिकरण मुआवजे के निर्धारण के लिए उक्त प्रतिशत को अपनाएगा। (उदाहरण के लिए, अरविंद कुमार मिश्रा बनाम अरविंद कुमार मिश्रा में इस न्यायालय के निर्णय देखें। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [(2010) 10 एससीसी 254: (2010) 3 एससीसी (सीआरआई) 1258: (2010) 10 स्केल 298] और यादव कुमार बनाम नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [(2010) 10 एससीसी 341: (2010) 3 एससीसी (सीआरआई) 1285: (2010) 8 स्केल 567]

37. सरनाम सिंह बनाम श्रीराम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने (2023) 8 एससीसी 193, आंशिक अक्षमता कब होगी इसका विश्लेषण करते हुए 100% कमाई क्षमता हानि होगी, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है: -

10. इस प्रकरण में जहां एक घायल की स्थायी अक्षमता उसकी कार्यात्मक अक्षमता को प्रभावित करती है, मुआवजे का आकलन कैसे किया जाना है, इस न्यायालय द्वारा बार-बार विचार किया गया है। मोहन सोनी बनाम राम अवतार तोमर [मोहन सोनी बनाम राम अवतार तोमर, (2012) 2 एससीसी 267: (2012) 1 एससीसी (सीआईवी) 747: (2012) 1 एससीसी (सीआरआई) 641] में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। उपरोक्त प्रकरण में घायल ठेला चालक के रूप में काम कर रहा था। दुर्घटना के परिणामस्वरूप, उसका बायां पैर काट दिया गया था। उनकी स्थायी अक्षमता का आकलन 60% किया गया था। न्यायाधिकरण ने मुआवजे का आकलन 50% पर करते हुए इस सिद्धांत पर किया कि वह अभी भी बैठकर कुछ अन्य काम कर सकता है। उच्च न्यायालय ने अक्षमता के कारण आय के नुकसान के संबंध में निष्कर्ष में कोई व्यवधान



नहीं डाला। इस न्यायालय ने पाया कि न्यायाधिकरण ने कमाई के नुकसान को 50% पर लेने में गलती की क्योंकि घायल की आयु 55 वर्ष थी और उस स्तर पर उसके लिए नौकरी ढूंढना मुश्किल हो सकता है। वास्तव में, किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी शारीरिक अक्षमता को अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति के संदर्भ में आंका जाना चाहिए। दो अलग-अलग व्यक्तियों को लगी एक ही चोट उन्हें अलग-अलग तरीकों से प्रभावित कर सकती है। जहां तक उसकी कमाई की क्षमता का संबंध है, किसी किसान या रिक्शा चालक द्वारा पैर की हानि सड़क का अंत हो सकता है। जबकि, कार्यालय में किसी प्रकार के डेस्क कार्य में लगे व्यक्तियों के प्रकरण में, पैर के नुकसान का कम प्रभाव हो सकता है। इस न्यायालय ने अर्जन क्षमता के नुकसान को 50% से बढ़ाकर 90% कर दिया।

11. प्रकरण में उसी सिद्धांत को लागू करते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता भारत होटल लिमिटेड के साथ एक बंदूकधारी के रूप में काम कर रहा था। घुटने के ऊपर उनका दाहिना पैर काटने के कारण, उन्हें 31-5-2015 से सेवा से समाप्त कर दिया गया था। यह विवाद का विषय नहीं है कि एक व्यक्ति जिसका दाहिना पैर कटा हुआ है, वह बंदूकधारी का कर्तव्य नहीं निभा सकता है। यह उसकी कार्यात्मक अक्षमता है। दुर्घटना के समय उनकी उम्र 50 साल और 5 महीने थी। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, न्यायाधिकरण अपीलकर्ता की कमाई क्षमता के नुकसान का 100% आकलन करने और तदनुसार मुआवजे का आकलन करने में सही था। उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले [श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सरनाम सिंह, 2017 एससीसी ऑनलाइन डेल 13011] पर भरोसा करते हुए कमाई की क्षमता के नुकसान को 80% तक कम करने में गलती की, इस मुद्दे पर इस न्यायालय का एक निर्णय उपलब्ध होने के बावजूद।

38. **पप्पू देव यादव बनाम नरेश कुमार (2022) 13 एससीसी 790** (तीन न्यायाधीशों द्वारा) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना से स्थायी अक्षमता के प्रकरण में भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए मुआवजा देने के मुद्दे पर विचार करते हुए, निम्नानुसार आयोजित किया: -

7. विचार के लिए दो प्रश्न उठते हैं: एक, क्या मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी अक्षमता के प्रकरण में, दावेदार भविष्य में आय के नुकसान के लिए मुआवजे के अलावा, भविष्य की संभावनाओं के लिए भी राशि की मांग कर सकता है; और दो, अक्षमता की सीमा। पहले प्रश्न पर,



उच्च न्यायालय निस्संदेह तकनीकी रूप से सही है कि प्रणय सेठी [नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी, (2017) 16 एससीसी 680: (2018) 3 एससीसी (सीआईवी) 248: (2018) 2 एससीसी (सीआरआई) 205] में उस प्रकरण में मुआवजे का आकलन शामिल था जहां पीड़ित की मृत्यु हो गई थी। हालाँकि, यह कहने में गलती हुई कि बाद में, जगदीश [जगदीश बनाम मोहन, (2018) 4 एससीसी 571: (2018) 3 एससीसी (Civ) 102: (2018) 2 एससीसी (Cri) 572] में तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय बाध्यकारी नहीं था, बल्कि यह कि अनंत [अनंत बनाम प्रताप, (2018) 9 एससीसी 450: (2018) 4 एससीसी (Civ) 378: (2018) 3 एससीसी (Cri) 756] में बाद का निर्णय इस हद तक कि उसने भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजा नहीं दिया, बाध्यकारी था। इस न्यायालय की राय है कि उच्च न्यायालय के लिए इस न्यायालय के पिछले फैसलों को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं था, ताकि गंभीर चोटों से जुड़े दुर्घटना के प्रकरण में भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजे की संभावना को बाहर किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी अक्षमता हो सकती है। प्रणय सेठी [नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी, (2017) 16 एससीसी 680: (2018) 3 एससीसी (सीआईवी) 248: (2018) 2 एससीसी (सीआरआई) 205] का ऐसा संकीर्ण पठन अतार्किक है, क्योंकि यह दुर्घटना के प्रकरण में जीवित पीड़ित के जीवन में आगे बढ़ने की संभावना को पूरी तरह से नकारता है? और पीड़ित की मृत्यु के प्रकरण में भविष्य की संभावनाओं की ऐसी संभावना को स्वीकार करता है।

39. सिद्राम बनाम डिवीजनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (2023)

3 एससीसी 439 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि गंभीर स्थायी अक्षमता के प्रकरण में, भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, जो निम्नानुसार है:-

31. अब यह कानून की एक अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी अक्षमता के प्रकरण में भी, दावेदार भविष्य में आय के नुकसान के लिए मुआवजे के अलावा, भविष्य की संभावनाओं के लिए भी राशि की मांग कर सकता है। हमने विभिन्न न्यायाधिकरणों के कई आदेशों का सामना किया है और दुर्भाग्य से विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, यह विचार रखते हुए कि दावेदार गंभीर चोटों से जुड़े दुर्घटना के प्रकरण में भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजे का हकदार नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी अक्षमता होती है। यह कानून की सही स्थिति नहीं है। गंभीर चोटों से जुड़े दुर्घटना के प्रकरण में भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजे की संभावना को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है,



जिसके परिणामस्वरूप स्थायी अक्षमता होती है। इस तरह का संकीर्ण पठन अतार्किक है क्योंकि यह दुर्घटना के प्रकरण में जीवित पीड़ित के जीवन में आगे बढ़ने की संभावना को पूरी तरह से नकारता है - और पीड़ित की मृत्यु के प्रकरण में भविष्य की संभावनाओं की ऐसी संभावना को स्वीकार करता है।

40. एफएफओ संख्या 2581/2011, सुशील कुमार और अन्य बनाम मेसर्स संपर्क लोजास्टिक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के प्रकरण में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने 26.04.2017 को फैसला सुनाया है कि भले ही दुर्घटना 26.09.2011 से पहले हुई हो, दावेदार यूपी मोटर वाहन नियमों के संशोधित नियम 220-ए के अनुसार भविष्य की संभावनाओं पर मुआवजे के हकदार हैं। 1998 में, चूंकि यह एक लाभकारी कानून है।

41. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि स्थायी अक्षमता के प्रकरण में, न्यायाधिकरण अक्षमता प्रमाण पत्र में उल्लिखित स्थायी अक्षमता की मात्रा से बाध्य नहीं है और इसे स्वतंत्र रूप से कार्यात्मक अक्षमता का आकलन करना होगा, नौकरी की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो दुर्घटना से पहले दावेदार द्वारा किया जा रहा था। प्रत्येक प्रकरण में, न्यायाधिकरण को यह आकलन करना होगा कि दुर्घटना के बाद, दावेदार वही काम करने की स्थिति में है, जो वह दुर्घटना से पहले कर रहा था।

42. संजय पीडब्लू-2 के साक्ष्य से, यह साबित हुआ कि दावेदार एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन के रूप में काम कर रहा था, जिसमें साड़ी, सूट सलवार, पैंट-शर्ट बेची गई थी और उसे 3,600/- रुपये प्रति माह का वेतन दिया गया था। हालांकि, न्यायाधिकरण ने पीडब्लू-2 द्वारा जारी वेतन प्रमाण पत्र पर अविश्वास किया है और दावेदार की मासिक आय 3000 रुपये आंकी है, जो पूरी तरह से उचित है, क्योंकि पीडब्लू-2 दुकान से अपनी आय का कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा।

43. यूपी मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 220-ए के अनुसार, स्थायी अक्षमता के प्रकरण में भी, दावेदार स्थायी अक्षमता के कारण भविष्य की आय के नुकसान के लिए 50% की दर से मुआवजा पाने का हकदार है, यदि वह दुर्घटना के समय 40 वर्ष से कम था।

44. यह स्पष्ट है कि अधिकरण द्वारा दावेदार को हुई अक्षमता के कारण भविष्य की आय की हानि के मद में कोई क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की गई है, जबकि दुर्घटना के समय उसकी आय मात्र



36 वर्ष थी। अतः **30प्र0 मोटर वाहन नियमावली, 1998 के नियम 220-ए** के अनुसार, वह 50% की दर से भविष्य की आय की हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी था।

45. पीडब्लू -2 के साक्ष्य से यह साबित हुआ कि दावेदार अपने परिधान की दुकान में एक विक्रेता के रूप में कार्यरत था, जिसे उसके द्वारा स्थायी अक्षमता के कारण दुर्घटना के बाद नौकरी से निकाल दिया गया था। यह स्पष्ट है कि, घुटने के नीचे अपने दाहिने पैर के विच्छेदन के कारण, दावेदार क्रॉस-लेग्ड बैठने, बार-बार खड़े होने या लंबे समय तक खड़े रहने में असमर्थ हो गया, जिसने उसे दुर्घटना के बाद एक सेल्समैन के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अयोग्य बना दिया, और इस कारण से, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसे देखते हुए, यह माना जाएगा कि दुर्घटना में लगी चोटों के कारण दावेदार को 100% कार्यात्मक अक्षमता का सामना करना पड़ा है।

46. **उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 के नियम 220-ए** के अनुसार, दावेदार दिए गए मुआवजे पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार था; हालांकि, न्यायाधिकरण ने इसे @ 6% प्रति वर्ष प्रदान किया है, जिसमें वृद्धि की आवश्यकता है।

47. यह भी स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण ने गैर-आर्थिक मदों के तहत मुआवजे की अपर्याप्त राशि का अधिनिर्णय दिया है, जिसके लिए शीर्ष न्यायालय के विभिन्न उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है।

48. उपरोक्त वैधानिक कानून और सर्वोच्च न्यायालय की मिसालों को ध्यान में रखते हुए, दावेदार को देय मुआवजे को निम्नानुसार पुनर्निर्धारित किया गया है: -

क्रम सं०	मुआवजे का मद	अधिनिर्णीत राशि (रु० में)	के अनुसार
1	दावेदार की मासिक आय	3000/-	जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है
2	दावेदार की वार्षिक आय	3,000X12= 36,000/-	जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है
3	भविष्य की संभावनाओं को @ 50% जोड़ें क्योंकि दावेदार	18000/-	30प्र0 मोटर वाहन नियमावली, 1998. पप्पू देव यादव (पूर्वोक्त) एवं सिदराम (पूर्वोक्त)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

	लगभग 36 वर्ष का था		
4	100% कार्यात्मक अक्षमता के कारण भविष्य की आय का कुल वार्षिक नुकसान	36,000+18,000=54,000/-	30प्र0 मोटर वाहन नियमावली, 1998. पप्पू देव यादव (पूर्वोक्त) एवं सिदराम (पूर्वोक्त)
5	दावेदार की आयु लगभग 36 वर्ष होने के बाद से लागू गुणक	15	प्रणय सेठी (पूर्वोक्त)
6	100% कार्यात्मक अक्षमता के कारण भविष्य में आय का कुल नुकसान	54,000X15=8,10,000/-	प्रणय सेठी (पूर्वोक्त) राज कुमार (पूर्वोक्त) एवं सरनाम सिंह (पूर्वोक्त)
7	दर्द, पीड़ा और सुविधाओं के नुकसान के लिए मुआवजा	1,00,000/-	-
8	विशेष आहार और परिवहन व्यय	25,000/-	-
9	उपचार का खर्च	38,000/-	जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है
10	कुल मुआवजा	9,73,000/-	

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

49. इस तरह, दावेदार दावा याचिका दायर करने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक @ 7% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 9,73,000/- रुपये के कुल मुआवजे का हकदार है, जिसे आपत्तिजनक बस संख्या यूपी-21एल-0405 के मालिक-यूपीएसआरटीसी द्वारा क्षतिपूर्ति की जानी है।

50. तदनुसार, यूपीएसआरटीसी द्वारा प्राथमिकता दिए गए एफएफओ संख्या 1698/2008 को खारिज कर दिया जाता है।

51. मुआवजे में वृद्धि के लिए दावेदार द्वारा प्राथमिकता दिए गए एफएफओ संख्या 2491/2019 को स्वीकृत किया जाता है। अधिकरण के दिनांक 17-03-2008 के अधिनिर्णय को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।

52. यदि यूपीएसआरटीसी द्वारा पहले किसी राशि का भुगतान किया गया है, तो वह तदनुसार राशि को समायोजित करने का हकदार है। यूपीएसआरटीसी को निर्देश दिया जाता है कि वह मुआवजे की बढ़ी हुई राशि को दो महीने के भीतर संबंधित न्यायाधिकरण के समक्ष जमा करे।

53. कार्यालय को एफएफओ संख्या 1698/2008 में अपीलकर्ता यूपीएसआरटीसी द्वारा किए गए वैधानिक जमा को संबंधित न्यायाधिकरण को तुरंत भेजने का निर्देश दिया जाता है।

54. एफएफओ संख्या 1698/2008 में यदि कोई अंतरिम आदेश हो तो उसे मुक्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

20 जनवरी, 2026

मयंक